**Irish Trade Delegation**

1406. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Irish trade delegation has expressed their keenness to have some joint ventures in their countries;

(b) whether they have invited Indian investment for the purpose;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the response made thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d). The Irish trade delegation had interaction with the Government as well as with businessmen. In the wake of liberalisation of Indian economy, both Irish and Indian sides considered cooperation in various sectors through trade, joint ventures and bilateral investments.

**गुजरात में बाल श्रम को समाप्त कराने में लगे स्वयंसेवी संगठन**

1407. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में बाल श्रम को समाप्त करने में लगे स्वयंसेवी संगठनों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या इन स्वयंसेवी संगठनों ने अपना विधिवत् लेखापरीक्षित तुलन-पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी):** (क) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात में होटलों, रेस्तराओं आदि में कार्यरत 150 बच्चों के लिए सर्वेक्षण और कल्याण परियोजना चलाने हेतु एक स्वैच्छिक संगठन को 47,000/- रु० की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) से (ङ) इस संगठन ने तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा लेखा परीक्षा किए गए लेखा का विवरण सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

**मसालों, चीनी और कृषि-उत्पादों पर लगाए उप-कर में छूट**

1408. **श्री सोमपाल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मसालों, चीनी और कृषि उत्पादों के निर्यात पर लगाए गए उप-कर में छूट देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस समय किन-किन वस्तुओं पर ऐसा उप-कर लगाया गया है और किन-किन वस्तुओं पर इसमें छूट देने का विचार है; और

(ग) ऐसी छूट दिये जाने का तर्काधार और औचित्य क्या है?

**वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम):** (क) मसालों, चीनी और कृषि उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले उप-करों में छूट एक सतत् प्रक्रिया है, जो निर्यात बाजार की दशाओं से जुड़ी हुई है।

(ख) केसर, इलायची, काली मिर्च (इनब्राइन हरी मिर्च को छोड़कर) और मसाला तेल तथा ओलिओरेजिन को छोड़कर कृषिजन्य उत्पाद उप-कर अधिनियम 1940, उत्पाद उप-कर अधिनियम, 1966 मसाला उपकर अधिनियम, 1986 तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 और एपीडा उपकर अधिनियम 1985 के अंतर्गत आने वाले सभी कृषिजन्य उत्पाद पर उपकर लगेगा।

चीनी पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और भारत में किसी भी चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर चीनी अधिनियम, 1982 के तहत उत्पाद शुल्क उपकर के रूप में लगाया और वसूला जाता है।

(ग) उपकर सहित निर्यातित सामान पर कर भार की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है विशिष्ट मदों पर छूट दी जाती है। लगने वाले उपकर में छूट देने से हमारा कृषिजन्य निर्यात विदेशी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है।

**Requirement and Production of Edible Oil**

1409. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the requirement of edible oil in the country as on date; and

(b) the production of edible oil in the country as on date; and

(c) the total imports of edible oil made

or proposed to be made during the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) and (b) The estimated requirement and net availability of edible oils from all domestic sources during the Oil Year (Nov.—Oct.) 1994-95 was 69.80 lakh MT and 64.00 lakh MT respectively.

(c) The import of edible oils (except coconut oil, palm kernel oil, RBD palm oil and RBD palm stearin) is allowed under Open General Licence. Central Government imports RBD palmolein for supply through the Public Distribution System (PDS). During the current financial year 1995-96 (upto October) the STC has imported 1.49 lakh tonnes of RBD palmolein for PDS.

**बाल श्रमिकों हेतु विद्यालय**

1410. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनन्य रूप से बाल श्रमिकों हेतु विद्यालय खोलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे बाल श्रमिकों के माता-पिता की आय में आई कमी की क्षतिपूर्ति करने का भी विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी):** (क) और (ख) श्रम मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (रा०बा०श्र०प०) स्कीम के अधीन, बालकों को कार्य से निकाला जाता है और उन्हें विशेष स्कूलों में भर्ती कर दिया जाता है जहां उन्हें प्राइमरी स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे छठी कक्षा से आगे के स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। इन बालकों को वृत्तिकाएं, पोषणाहार और स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान की जाती है। विशेष स्कूलों की स्थापना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अधीन एक प्रमुख क्रियाकलाप है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत कार्य से निकाले गए और विशेष स्कूलों में भर्ती कराए गए बालकों को 100 रुपए की वृत्तिका प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कार्य जगत से निकाले गए बालकों के माता-पिता के आय-स्तरों को सरकार की अन्य स्कीमों के माध्यम से ऊपर उठाने की परिकल्पना की गई है। इन स्कीमों में अन्यों के साथ-साथ आई आर डी पी, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं को उचित रूप से अभिकेन्द्रित करने के लिए, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में "राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकरण का गठन किया गया है।

**Suppy of Essential Commodities to Maharashtra**

1411. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the supply of essential commodities made to the State of Maharashtra monthwise for the last one year vis-a-vis the demand made/requirement, commodity-wise and the basis for release of the quota;

(b) whether the Government of Maharashtra made some proposal to the Central Government for allotment of kerosene;

(c) if so, details of action taken/proposed thereon; and

(d) the details of major policy changes sought by the State Government and action taken/proposed thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (c) The details showing the allocation and offtake of commodities for the Public Distribution System (PDS) in